

Port congestions

405. SHRI MADHEVRAO SCINDIA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that port congestion have resulted in hampering the import of edible oil which is waiting berths in ship for more than 4 months;

(b) if so, whether it is also a fact that the preference for reservation of berths in ship is given to fertilizers and petroleum over other items including edible oils; and

(c) if so, what steps are being taken to bring the imported edible oil in ships at the shortest possible time?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) No edible oil vessel has been waiting for berthing for four months or more at any of the major ports.

(b) and (c). Do not arise.

बंदुका श्रमिकों का पुनर्वास

406. श्री शैल प्रकाश त्वाणी : क्या संसदीय कार्य तथा भव, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1978 के बाद, जब से सरकार ने देश में बंदुका श्रम पर प्रतिबन्ध लगाया है, विभिन्न राज्यों में कितने बंदुका श्रमिकों को मुक्त किया गया है ;

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस बीच कितने बंदुका श्रमिकों का पुनर्वास किया गया है ; और

(ग) शेष बंदुका श्रमिकों का पुनर्वास कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग-साय) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है जिसमें व्योरा दिया गया है ।

(ग) यद्यपि समस्या की जटिलता को देखते हुए, कोई समय-अनुसूची निर्धारित नहीं की जा सकती है, तथापि, मुक्त कराए गए बंदिन श्रमिकों के पुनर्वास के लिए, यथा संभव प्रयास किए जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 2 करोड़ रुपये के परिव्यय की केन्द्र संचालित योजना की परिकल्पना की गई है, जिसमें से प्राधी राशि वार्षिक योजना व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को बराबर-बराबर अनुदान (मेचिंग ग्राण्ट) देने के माध्यम पर है । राज्य सरकारों को भी मुक्त कराये गये बंदिन श्रमिकों के शीघ्र पुनर्वास के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती है ।

विवरण

31-12-1978 तक राज्य सरकारों द्वारा बेची गई सूचना के अनुसार स्थिति

क्रमांक	राज्य	बंदिन श्रमिकों की संख्या		
		पता लगाए गए	मुक्त कराये गए	पुनःवासित किए गए
1		2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	10,518	10,452	7,304
2	बिहार	2,857	2,857	613
3	उत्तराखण्ड	64,042	64,042	†(30,557) (7,804)